सरकारी योजनाएं

एक गाइड बुक, आम लोगों के लिए

जुलाई 2025

7 कदम एक समुदाय को बेहतर बनाने के लिए

यह छोटी किताब आम इंसान के जीवन और उनके समुदाय को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। सरकार ने हम सभी के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई हैं। यह सुविधाएं मिलना सब लोगों का अधिकार हैं चाहे वे गांव, शहर या बस्ती में रहते हैं। लेकिन यह सुविधाएं आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि

- बहुत से लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते ,
- बहुत से लोगों के पास प्रयाप्त दस्तावेज नहीं होते ,
- अक्सर लोगों के पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं होता है , या
- कभी–कभी लोग सरकारी अफसरों के पास जाने से डरते हैं।

इसलिए सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आम लोग दलाल के पास जाने को मज़बूर होते हैं और पैसा देते हैं जबकी सुविधाएं मुफ़्त होने चाहिए । यह किताब 7 कदमों में दर्शाती हैं कि आप और आपके साथी कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं: दलाल के बिना । यह 7 कदम इस प्रकार हैं :

1. अपने अधिकारों को जानें, कानूनों और योजनाओं के तहत
2. यह तय करें कि किस अधिकारों के लिए पहले आवेदन करें
3. एक आवेदन जमा करें (अच्छा हो कि आवेदन ऑनलाइन हो)
4. सरकारी अधिकारी के साथ अच्छी तरह से बात करें
5. अगर आवश्यक हो, तो उच्च प्राधिकरण के पास ले जाएँ। (RTI के द्वारा)
6. अगर सफ़लता न मिले तो अपने काम का मूल्यांकन करें
7. सफ़लता मिलने पर सब के साथ खुशी मनाए

1. अपने अधिकारों को जानो (जुलाई 2025 को)

मुद्दा	**आपके अधिकार** (**कानून**, जो *सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में*) (**योजना**, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	**आवेदन** कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	**कितना मुश्किल** (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
खाना				
1. खाद्य सुरक्षा 	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 3(1) and Schedule 1) 'प्रधान्य परिवार' के प्रति व्यक्ति को 5 किला अनाज प्रति महीना रू 2 गेहूं , रू 3 चावल 35 किलो प्रति बहुत गरीब परिवार को प्रति महीना	**कहॉ:** स्थानीय CSC/JSK यहां **शुल्क:** CSC/JSK यहां में रु100 **दस्तावेज:** (यहां देखें) आधार (सब परिवार के सदस्यो के लिए), आय प्रमाण पत्र (1 लाख से कम), फोटो, महिला मुखिया का बैंक खाता।	मध्यम 1 महीना	खाद्य एंव आपूर्ति विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय ऑन लाइन शिकायत यहां
2. ऑगनवाड़ी 	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 5(1)a) बच्चें (6 साल से कम) के लिए, एक आंगनवाड़ी जिसमें अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है	**कहॉ:** सीानीय आंगनवाड़ी **शुल्क:** शून्य यदि आंगनवाड़ी नहीं है, तो शुरू करने के लिए आवेदन करेंरू **कहॉ: स्थानीय महिला एवं बाल विकास कार्याल** **दस्तावेज:** 3 से 6 वर्ष के 40 बच्चों की सूची के साथ (यहां पर RTF पृष्ठ 7 देखें)।	मुश्किल से 6 महीने	महिला एवं बाल विकास विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. मध्यान्तर भोजन 	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 5(1)b) कक्षा 8 तक के हर बच्चे को स्कूल में हर दिन (200 दिन साल में) अच्छा खाना	**कहॉ:** सीानीय स्कूल प्रिंसिपल के पास **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** कुछ नहीं	मध्यम 1 महीना	मिड डे मील ऑथोरिटी का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
कागज़ात				
1. आधार कार्ड	योजना: भारत आधार आयोग वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें किसी भी भारतीय निवासी के लिए मुख्य पहचान पत्र। बॉयोमीट्रिक्स जानकारी शामिल है जो कि समय–समय पर अपडेट होती है, 5 साल और 15 साल	**कहॉ: स्थानीय** आधार **केंद्र पर। नियुक्तियाँ प्राप्त करें और स्थिति की जाँच करें** यहाँ **शुल्क:** नामांकन 0, विवरण रु 50, बॉयोमीट्रिक्स रु 100 **दस्तावेज:** पता और उम्र के सबूत। सूची यहां।	आसान 1 महीना	भारत आधार आयोग UIDAI का राज्य प्रमुख कार्यालय (यहां देखें और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पृष्ठ के नीचे स्क्रॉल करें)।
2 आय प्रमाणपत्र:	योजना: आय प्रमाणपत्र: राशन कार्ड, पेंशन, बालिका भुगतान, आवास योजना आदि के लिए आवश्यक	**कहॉ:** स्थानीय CSC/JSK यहां **शुल्क:** CSC/JSK यहां में रु100 से 300 तक **दस्तावेज:** यहां आधार, 2 फोटो, पार्षद पत्र	मध्यम 2 हफ्ते	ज़िला मैजिस्ट्रट
3. पैन कार्ड	योजना: पैन कार्ड वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें यदि आयकर का भुगतान करना अनिवार्य है गैर करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है।	**कहॉ:** ऑन लाइन यहां देखें या CSC/JSK यहां **शुल्क:** रु 107 **दस्तावेज:** आधार, 2 फोटो	आसान 1 महीना	आयकर विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
4. मतदाता पहचान पत्र	योजना: भारत का चुनाव आयोग वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें हर भारतीय जिसकी उम्र 18 से ऊपर हैं को पहचान पत्र मिलें। फिर उस व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र मिल सकता हैं ।	**कहॉ:** ऑन लाइन यहां देखें या CSC/JSK यहां **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** फॉर्म 6, पता के सबूत और उम्र के सबूत (यदि 21 साल से कम है) के सबूत	मध्यम 1 महीना	राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी
5. बैंक खाता	योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें 10 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है।	**कहॉ:** कोई भी बैंक से संपर्क करें **शुल्क:** PMJDY शून्य, नहीं तो रु500–1,000 **दस्तावेज:** यहां आधार, 2 फोटो	मध्यम 15 दिन	बैंक जिस पर आपने आवेदन किया, उसका राज्य प्रमुख कार्यालय
6. जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र	कानून: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 8 & 12) भारत में पैदा हुए किसी भी बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र भारत में मरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र	**कहां:** अगर जन्म पंजीकृत हो, तो नगर निगम, अगर पंजीकृत नहीं हो, तो एसडीएम से संपर्क करें **शुल्क:** शून्य (सरकारी अस्पताल), रु100 (निजी) **दस्तावेज:** जन्म प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल, शून्य निजी में, तो आधार और निर्वहन पर्ची	मध्यम 1 महीना	ज़िला मैजिस्ट्रट
7. जाति प्रमाण पत्र	योजना: जाति प्रमाण पत्र वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय के लिये, प्रमाण पत्र	**कहॉ:** उपमंडल मजिस्ट्रेट के पास जाएं **शुल्क:** CSC/JSK यहां में रु300 **दस्तावेज:** आधार, जाति पर शपथ पत्र	मध्यम 3 महीने	ज़िला मैजिस्ट्रट
8. श्रम कार्ड	कानून: भवन निर्माण अन्य निर्माण कामगार अधिनियम 1996 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 12) निर्माण उद्योग में कोई भी, 18–60 साल है और वास्तव में पिछले 12 महीनों में 90 से अधिक दिनों के लिए काम किया हो उसको श्रम कार्ड मिल सकता है।	**कहॉ:** कुछ राज्यों में ऑन लाइन जैसे यू पी यहां **शुल्क:** CSC/JSK यहां में रु100 **दस्तावेज:** यहां आधार, बैंक खाता, 2 फोटो, रोजगार के सबूत।	मध्यम 1 महीना	श्रम विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	**आपके अधिकार** (**कानून**, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (**योजना**, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	**आवेदन** कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	**कितना मुश्किल** (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
आय				
1. मनरेगा 	**कानून: राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 3(1) हर ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिन रोज़गार कम से कम 234 रुपये प्रति दिन (यहां देखें)	**कहॉ:** सीनीय ग्राम पंचायत **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** आधार	मध्यम 2 महीने	ग्रामीण विकास विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
2. पेंशन 	**योजना: राष्ट्रीय समाज सहायता योजना** वेबसाइट के लिए **यहां** क्लिक करें (See page 4) 60 वर्ष से अधिक (बी पी एल) वृद्धा के लिए कम से कम रु 200 पेंशन 40 से 79 वर्ष (बी पी एल) वृद्धजनों के लिए कम से कम रु 300 पेंशन बहुत से राज्य में रु 500 या उससे अधिक हैं	कहां: कुछ राज्यों में ऑनलाइन या CSC/JSK यहां या तहसील या समाज कल्याण वभाग में **शुल्क:** शून्य **पर आय प्रमाण पत्र 200** **दस्तावेज:** (फॉर्म यहां देखें) पार्षद पत्र, आधार, बैंक खाता, फोटो, आय प्रमाणपत्र: (विधवा के लिए 2 लाख से कम, वृद्धावस्था विकलांगता के लिए 56,000 से कम) विधवा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग के लिए विकलांग प्रमाण पत्र	मध्यम 3 महीने	समाज कल्याण विभागराज्य का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. बच्ची के लिए पैसे 	**योजना: बालिका समृद्धि योजना** वेबसाइट के लिए **यहां** क्लिक करें सरकार लड़की के जन्म के वक्त, परिवार के खाते में रु500 जमा करती हैं। सिर्फ पहली दो लडकियों के लिए लागू शिक्षा के हर कदम पर, राशि बढ़ती रहती है लडकी 18 साल तक शादी ना होने पर, पैसा निकाल सकते है।	बालिका समृद्धि योजना **कहॉ:** स्थानीय आंगनवाड़ी **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** आधार, बैंक खाता, जन्म प्रमाणपत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र, फोटो।	मध्यम 1 महीना	महिला एवं बाल विकास विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
4. जीवन बीमा 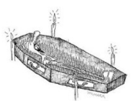	**योजना: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** वेबसाइट के लिए **यहां** क्लिक करें (See page 4) रु30,000 (यू पी मॅ) परिवार जिसके कमाने वाला (जो 60 वर्ष से कम) की मृत्यु हो गई).	**कहॉ:** स्थानीय समाज कल्याण विभाग **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** (फॉर्म यहां देखें) आधार, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र (शहरी 56 से कम, ग्रामीण 46 से कम) कमाने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार	मध्यम 2 महीने	समाज कल्याण विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
स्वास्थ्य				
1. आर. एस. बी. वाई 	**योजना: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (आयुष्मान भारत भी कहा जाता है) सबसे कमजोर परिवारों के 500 करोड़ लोगों के लिए 5,00,000 रुपये का इलाज **योजना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** वेबसाइट के लिए यहां (see p 6,7) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 डाक्टर होना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2	**प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए** कहां: ऑन लाइन यहां या इस App पर यदि आप पात्र है, (सब लोग जो 60 साल) किसी भी सरकारी अस्पताल में जाये **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज़:** आधार,	मध्यम 1 महीना	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यहां देखें
2. दवाएँ	**योजना: प्रधानमंत्री जन औषधि योजना** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें गंभीर रूप से छूट वाले औषधियाँ	कहाँ स्थानीय जन औषधि स्टोर (अक्सर सरकारी अस्पतालों में स्थित) **शुल्क:** दवाओं पर 10–60: छूट	आसान 1 दिन	फार्मास्यूटिकल्स विभाग यहाँ
3. गर्भवजी एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं 	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** वेबसाइट के लिए यहां (See Sec 4(a) and 4(b)) और यहां (See Sec 2) हर एक गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी से मुफ्त खाना मिलता हैं । अस्पताल में पहली बच्चे रू 5,000, और ₹6,000 दूसरी लड़की के लिए।	**कहॉ:** स्थानीय आंगनवाडी, आशा, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** कुछ नहीं	मध्यम 1 महीना	ज़िला अस्पताल का सी एम ओ
4. टीकाकरण 	**योजना: योजना: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें सइ बच्चे के लिए, टी बी, पोलियो, हेपिटाइटस बी, डी.पी.टी., और चेसक का टीकाकरण, मफ्त में	**कहॉ:** स्थानीय आंगनवाडी, आशा, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र **शुल्क: शून्य** **दस्तावेज:** कछ नहीं	आसान 1 हफ़्ता	ज़िला अस्पताल का सी एम ओ
5. टी बी इलाज	**योजना: डोटस** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें टी बी के मरिजो के लिए, मुफ्त जांच और इलाज **योजना: एनपीवाई** इलाज के दौरान प्रति माह रु1,000। यहां	**कहॉ:** पास का कोई **डोटस** केंद्र यहां **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज़:** आधार, बैंक खाता	आसान 2 हफ़्ते	जिला टीबी अधिकारी यहां देखें राज्य टीबी अधिकारी यहां देखें टीबी हेल्पलाइन 1800 11 6666
6. विकलांग व्यक्ति 	**कानून: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016** वेबसाइट के लिए यहां (See Sec 2(r)) क्लिक करें पेंशन कम से कम रू 300/माह यदि 40% विकलांगता, बीपीएलए, 18 साल यहां **योजना: यूनिक डिसाबिलिटी आईडी यूआईडी,** (यहां क्लिक करें) विकलांगता के लिए पहचान पत्र	**पेंशन कहॉ:** कुछ राज्यों में **ऑनलाइन** (या SC/JSK नही तो, व्यक्ति द्वारा तहसील या समाज कल्याण में **शुल्क: शून्य पर आय प्रमाण पत्र 200** **दस्तावेज़: फार्म** यहां आधार, **आय प्रमाण पत्र (56,000)** यूआईडी, ऑनलाइन यहां **दस्तावेज:** आधार, फोटो, विकलांग प्रमाण पत्र	मध्यम 3 महीने	समाज कल्याण विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
7. मानसिक स्वास्थ्य 	**कानून: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के अच्छे और सस्ते इलाज का अधिकार (सरकारी, या सरकारी वित्त पोषित अस्पतालो में)	**कहॉ:** पास वाला सरकार (या सरकारी वित्त पोषित) मानसिक स्वास्थ्य सुविधा **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** कुछ नहीं	मध्यम महीना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	**आपके अधिकार** (**कानून**, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (**योजना**, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	**आवेदन** कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	**कितना मुश्किल** (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
शिक्षा				
1. स्कूल 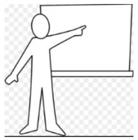	**कानूनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 3, 12(b) & 25) आठवी तक बिलकुल मुफ़्त शिक्षा (Sec 3) हर 35 बच्चें के लिए 1 अध्यापक होना चाहिए (Sec 25) निजी स्कूलों (जो सरकारी सहायता प्राप्त हैं) गरीबों को 25% सीटें मुफ्त में देनी चाहिए (Sec 12(b))	**आम प्रवेश** **कहॉ:** पास वाला सरकारी स्कूल **दस्तावेज:** शून्य **निजी स्कूल में ईडब्ल्यूएस प्रवेश** **कहॉ:** ऑन लाइन यहां क्लिक करें **शुल्कः** शून्य **दस्तावेज:** जन्म–प्रमाणपत्र आय–प्रमाणपत्र	मध्यम 1 महीना	शिक्षा विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
2. शिक्षा का लाभ 	**कानूनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम** वेबसाइट के लिए यहां किताब और वार्दी मुफ़्त है आठवी तक विभिन्न छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां यहां	**कहॉ:** पास वाला वाला सरकारी स्कूल **शुल्कः** शून्य छात्रवृत्तियां **कहॉ:** ऑन लाइन यहां **दस्तावेज वेबसाइट पर सूचीबद्ध**	मध्यम 2 महीने	शिक्षा विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 	**योजनाः राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें सस्ती दूरस्थ शिक्षा (स्कूल जाने के बिना) सभी के लिए 12वीं तक *Open Basic Education (A)=Std 3, OBE(B)=Std 5, OBE(C)=Std 8, *Secondary (Std 10), Senior Secondary (Std 12)	**कहॉ:** ऑन लाइन यहां क्लिक करें या स्थानीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान केंद्र **शुल्कः** यहां रु2,600 तक (ट्यूशन छोड़कर) **दस्तावेज:** आधार, फोटो, मार्क्स शीट कक्षा 10 के लिए आत्म–घोषणा पर्याप्त है।	आसान 1 महीना	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा का राज्य प्रमुख कार्यालय
बिजीलि व गेस				
1. बिजली 	**सौभाग्य (बंद किया जा सकता है)** वेबसाइट यहां के लिए यहां क्लिक करें कनेक्शन के लिए पात्र सभी अविद्युतीकृत परिवार	**कहां:** राज्य डिस्कॉम सें संपर्क करें **शुल्कः 10 मासिक किस्तें रु50 =रु500** **दस्तावेज:**अलग–अलग राज्यो के लिए अलग–अलग	मध्यम 3 महीन	बिजली देने वाली कम्पनी (जिसको आपने आवेदन किया) उस राज्य का प्रमुख कार्यालय
2. गैस कनेक्शन 	**योजनाः उज्जवला 2.0** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें हर घर जिसमें खाना पकाने की जगह अलग और पक्का स्ओव हो उस घर को एक गैस कनेक्शन मिल सकता है। सब्सिडी वाले कनेक्शन के लिए पात्र कोई भी गरीब वयस्क महिला	**कहॉ:** स्थानीय इंडेन या भारत गैस सें संपर्क **शुल्कः** लगभग रु.4,500 **दस्तावेज:** (फॉर्म यहां देखें) राशन कार्ड, आधार, (KYC फॉर्म यहां देखें) बैंक खातो	मध्यम 15 20 दिन	अधिभरे हुए गैस के लिए स्थानीय गैस आपूर्तिकर्ता (तराजू का उपयोग अन्य मुद्दे_इण्डेन या भारत गैस (जिसको आपने आवेदन किया) का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
गॉव सुवीधाऐं				
1. शौचालय / लैट्रीन 	**योजना: निर्मल भारत अभियान (ग्रामीण)** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें पक्की लैट्रीन बनाने के लिए रु 12,000 की सबसिडी **योजना: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See 4.4 on page 13) पक्का लैट्रीन बनाने के लिए रु 4,000 की सबसिडी	**कहां: ग्रामीण:** स्थानीय ग्राम पंचायत **शहरी:** ऑन लाइन यहां या स्थानीय CSC/JSK **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** आधार, बैंक खाता, फोटो	मध्यम 3 महीने	ग्रामीण: मंत्रालय पेयजल स्वच्छता यहां देखें शहरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यहां देखें
2. खड़न्जा और नालिया 	**योजना: ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See 3.2 on page 17) ग्रमीण स्वास्थ्य, स्वच्छता **एवं पोषण** समिति को रु10,000 हर साल मिलते है गॉव के विकास, जैसे खडंजा, नालियॉ और साफ–सफाई के कार्यो के लिए	**कहॉ:** स्थानीय ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति से संपर्क करें **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** ?	मुश्किल 6 महीने	लोक स्वास्थ्य इजीनियरिंग विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. मकान 	**योजना ग्रामीण: प्रधानमंत्री आवास योजना** ग्रामीण वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see pviii (#5) & p27 (5.1.1) गरीब ग्रामीण परिवारों को घर बनाने लिए रु.1,20,000 **योजना (शहरी): लाभार्थी की देख –रेख में निर्माण (बीएलसी)** शहरी वेबसाइट के लिए यहां ओर यहां यदि आपके पास ज़मीन है, तो निर्माण करने के लिए 1,50,000 रुपये तक का प्रावधान	**ग्रामीण: (पी एम ए वाई)** **कहां:** पंचायत या बी डी ओ या जिला डीडी ओ **शुल्क:** शून्य **शहरी: लाभार्थी देख –रेख में निर्माण (BLC)** **कहां:** CSC/JSK यहां **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** प्रमाण पत्र (आय, निवास और जाति निवास), भूमि रजिस्ट्री, शपथ पत्र आदि।	मुश्किल 1 साल	ग्रामीण: ग्रामीण विकास मंत्रालय यहां देखें शहरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यहां देखें
4. भूमिहीनों के लिए भूमि 	**योजना (शहरी): सस्ता आवास साझेदारी में (AHP)** वेबसाइट के लिए यहां पर क्लिक करें (See #6 Page 9) बड़ी सब्सिडी वाला सरकारी फ्लैट। आमतौर पर लॉटरी से तय होता है।	**साझेदारी में किफायती आवास (ए एच पी)** **कहां:** स्थानीय CSC/JSK यहा महिला द्वारा आवेदन करना बेहतर है । **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** आधार, बैंक खाता	बहुत मुश्किल 1 साल से ज्यादा	ग्रामीण: ग्रामीण विकास मंत्रालय यहां देखें शहरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यहां देखें
5. सड़कें 	**योजना: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see page 1 Sec 1.2) हर गांव जिस में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं (पहाड़ी इलाको में 250) तक पक्की सड़क ।	कहॉ: स्थानीय लोक निर्माण विभाग से संपर्क करें **शुल्क:** शून्य दस्तावेज: ?	मुश्किल 1 साल	ग्रामीण: ग्रामीण विकास मंत्रालय यहां देखें

मुद्दा	**आपके अधिकार** (**कानून,** जो *सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में*) (**योजना**, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	**आवेदन** कहॉ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रुरी दस्तावेज़	**कितना मुश्किल** (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	जहॉ शिकायत कर सकते
मानव अधिकार				
1. घरेलू हिंसा 	**कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति अधिनियम 2005** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 3) किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा (मारना, तंग करना, खाना ना देना, धमकी देना, गाली, दहेज मांगना) सख्त मना हैं ।	**कहॉ:** स्थानीय पुलिस थाना सें संपर्क करें **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** शून्य	मध्यम 2 हफ्ते	राज्य महिला आयोग यहां देखें
2. बाल मज़दूरी 	**कानून: बाल श्रम अधिनियम 1986** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 3, 7 and FAQ 16 यहां) 14 साल से कम बच्चे से किसी भी खतरनाक काम (जैसे ढाबों, घरेलू काम, पटाखे की फैक्ट्री) में काम करवाना गैरकनूनी हैं। दिन में 6 घंटे से ज्यादा नहीं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई काम नहीं कराया जा सकता	**कहॉ:** 1098 मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर पर फ़ोन करें **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** शून्य	मुश्किल 2 हफ्ते	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें
3. बाल शादी 	**कानून: बाल शादी अधिनियम 2006** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 2 & 11) और यहां लड़का 21 वर्ष से कम और लड़की 21 वर्ष से कम शादी गैरकानूनी है जो बाल शादी करवाता है उसके लिए सजा का प्रावधान है	**कहॉ:** 1098 मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर पर फ़ोन करें **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** शून्य	मुश्किल 2 हफ्ते	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें
4. तस्करी वेश्याव्ृत्ति 	**कानून: तस्करी वेश्याव्ृत्ति अधिनियम 1956** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 5 & 17) तस्करों को आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती। (Sec 5) नाबालिग बच्ची को बाल कल्याण समिति द्वारा देख–रेख में दिया जा सकता है। (Sec 17)	**कहॉ:** स्थानीय पुलिस थाना सें संपर्क करें **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** शून्य	मुश्किल 6 महीने	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें
5. तस्करी बंधुआ मज़दूर 	**कानून: बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976** वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 4) बंधुआ मज़दूरी निषेध है। बंधुआ मज़दूरों कर्ज से मुक्त किया जाता है। बंधुआ मज़दूरों को मुआवज़ा दिया जाता है। समाज में फ़िर दोबारा जोड़ना की मदद।	**कहॉ:** ज़िला विजीलेंस समिति सें संपर्क करें **शुल्क:** शून्य **दस्तावेज:** शून्य	मुश्किल 6 महीने	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें

2. किस अधिकार के लिए आवेदन करें ?

एक जन के आधिकार: कुछ आधिकार जैसे पेंशन या राशन कार्ड से, सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को फ़ायदा होता हैं और उनका मिलना थोड़ा आसान भी है। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे है तो आप इस किताब के 3 – 7 कदम द्वारा अपनी समस्या हल कर सकते है। फिर आप भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं ।

समुदाय के आधिकार: इसके अलावा कुछ समस्याएं, जैसे बिजली या साफ़ पानी की कमी, पूरे गॉव या बस्ती पर असर करती हैं । इन समस्याओं को हल करना थोड़ा मुश्किल हैं, इसलिए पूरे समुदाय को मिल कर काम करना होगा और साथ मिलकर इन्हे सुलझाना होगा। अगर आपके गाँव या बस्ती में ऐसी कोई समस्या हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बैठक करे और मद्दे पर चर्चा करे । याद रखे इस मीटिंग में :

- **सभी की बात सुने:** आमतौर पर सिर्फ बड़े बड़े लोग ही ऐसी बैठकों में उपस्तिथ रहते है, मगर आप सभी लोगों को पूरा महत्व दे। इसलिए कोशिश करे की बैठक में बच्चे, बूढ़े, महिलाए, विकलांग और गरीबों की उपस्तिथि हो । यदि आप उन्हें जानते हैं तो पंचायत सचिव, वार्ड पंच या सरपंच को भी आमंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि वे सहायक हो सकते हैं।
- पहले से ही आप **किसी ऐसे व्यक्ति को चुन** ले जिसकी समुदाय में अच्छी पकड़ हो और सभी लोग उसकी सुनते हो और इ़ज्जत करते हो, इससे आपको बैठक को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **सब लोगों की बातें ध्यान से सुने:** जो भी उन्होंने बोला, आप उसे दोबारा दोहराए ताकि वह ये जान पाए कि आप उनकी बाते समझ गए है ।
- **किसी को ज़्यादा न बोलने दे:** वर्ना दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा । अगर कोई ज़्यादा बोल रहा हैं, उस की बात और भी ज़्यादा दोहराओ, ताकि वह जान ले कि आप उसे सुन रहे है और वह अपने आप खामोश हो जाए ।
- उम्मीद हैं कि फ़ैसला हो जाएगा कि **किस समस्या को पहले हल करें** । अगर ज़रूरी हो, वोट कर सकते हैं, मगर वोट हारने वाले निराश हो सकते हैं । बेहतर हो कि समझौते से सब लोग – छोटे – बड़े – उस समस्या को पहले हल करने के लिए तैयार हो ।

<u>उस समस्या को चुने जो :</u>

- आपके ज़िले में किसी दूसरे गॉव या बस्ती ने इस ऐसी समस्याओं को हल किया हैं।
- हल करने में कम पैसा लगेगा।
- हल करने में कम समय लगेगा।
- हल करने में कोई दुशमन न बनेंगे। (जैसे की जुआ, शराब इस तरहॉ की चीज़ो पर रोक लगाने से दुश्मन बन सकते है।)
- काफी जरूरी है: जैसे एक नई सड़क से पहले, एक बहुत बीमार रोगी का इलाज करवों क्योंकि यह अधिक जरूरी है।
- ज़्यादा लोगों पर असर पड़े।
- हल करने के लिए लोगों में काफ़ी जोश हों ।

3. अधिकार मिलने के लिए आवेदन करना

अगर हो सके है, तो ऑन लाइन आवेदन करें ताकि **अनधिकृत भुगतान** मांगने का मौका न हो, जैसे कि पेंशन यहां। कई गांवों में एक कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र (यहां देखें) होता है, जहां आप कुछ पहचान दस्तावेजों और अन्य योजनाओं के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं । बिहार, राजस्थान, यूपी और एमपी में आप स्थानीय जन सेवा केंद्र का इस्तेमाल कर सकते हैं (यहां देखें) । कुछ आवेदन विशेष फ़ॉर्म की आवश्यकता होती है जोकि दफ़्तरों में उपलभ होते हैं।
अगर फ़ॉर्म न मिल तो, खाली कागज़ पर अपना आवेदन लिखे । आपके आवेदन में ज़रूर निमलिखित 4 बाते होनी चाहिए :

1 **अपनी समस्या को साफ बताइए।** जैसेः आपके गॉव में आंगनवाडी नहीं है। अगर समस्या का फोटो भी हो, तो उसे भी चिपका दीजिए। इससे आवेदन और भी अच्छा बनेगा ।

2 **अपने अधिकार,** और किस कानून या योजना से यह अधिकार मिलता है (तलिका में हरे खाने को देखिए)। जैसेः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 (1) (ए) के तहत, यहां सरकार को 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी प्रदान करनी चाहिए।

3 **अपनी मॉग साफ़ बताइए यानी** आपको क्या चाहिए, कब तक, जेसेः आप चाहते हैं कि 30 जून 2021 तक एक आंगनवाड़ी की स्थापना हो। (तलिका में नीले खाने को देखिए)

4 **अगले कदम।** साफ़ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या अगले कदम लेंगे। जैसेः अगर 30 जून 2021 तक आपके गांव में आंगनवाड़ी न हो, तो हम आर टी आई।

अपने आवेदन की एक कॉपी मुख्य कार्यालय (बड़े अफ़सर) (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए) को भी भेज देना । फ़िर शायद छोटा अफ़सर बात मान कर जल्दी काम कर दे।
आवेदन लिखकर आप सही सरकारी दफ़्तर को डाक से भेज सकते हैं (तलिका में पीले खाने को देखिए) । अगर आप यह करें तो, रेजिस्टरड पोस्ट के द्वारा ही अपना आवेदन भेजें, और रीसीट सुरक्षित रख ले, ताकि आप दिखा सकते हैं कि किस दिन यह भेजा गया था। आवेदन का नमूना नीचे दिया गया हैः

सेवा में
समेकित बाल विकास योजना
ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
1 जुलाई 2025

शिवारामपुर के लिए आंगनवाडी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 (1) (ए) के तहत

महोदय,
मैं शिवरामपुर, ज़िला फतेहपुर का निवासी हूँ । मे सम्मानपूर्वक निम्नलिखित बताता हूं: –

1 हमारे गांव की आबादी 2,350 है, जिनमें से 6 महीने से 6 साल के बीच की उम्र के 272 बच्चे हैं। अभी तक हमारे गॉव में कोई आंगनवाडी नहीं है। मैं अपने गांव में इस उम्र के बच्चों की एक सूची संलग्न की है, साथ में उनकी एक फ़ोटो भी है ।

2 मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 (1) (ए) के तहत, (यहां देखें) सरकार को 6 महीने से लेकर 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी प्रदान करनी चाहिए।

3 इसलिए मैं अपने गांव के लिए कई आंगनबाड़ियों के लिए आवेदन करना चाहूंगा । मैं चाहूंगा कि ये आंगनबाड़ियां 31 दिसम्बर, 2025 तक शुरू हो जाएं।

4 अगर 31 दिसम्बर, 2025 तक आंगनबाड़ियां न हो, तो मैं आर टी आई डालूंगा, मालुम करने के लिए कि मेरा आवेदन को क्या हुआ ।

रामेश कुमार,
मकान न 6, गली न 7, शिवारामपुर गॉव, ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, टेलीफोन 9750 478 598
हमने यह आवेदन उत्तर प्रदेश का समेकित बाल विकास योजना का प्रधान कार्यालय को भी भेजा हैं ।

4. सरकारी अधिकारी के साथ अच्छी तरह से बात करें

कभी कभी, सरकारी अधिकारी से मिलना, या आवेदन देने के लिए, या उसकी प्रगति पर जांच करने के लिए, ज़रुरी होता है । यदि आप सरकारी अधिकारी से मिलें, तो ये बाते पर ध्यान रखेः

मीटिंग से पहले अच्छी तैयारी करो

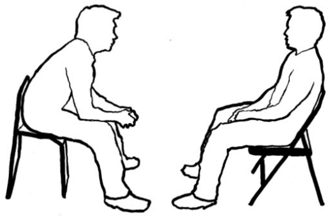

- अपने साथ किसी आस–पड़ोस के व्यक्ति को साथ ले कर जाए। यदि कोई **अनधिकृत भुगतान** मॉगता हैं तो वह गवाह बन सकता है।
- मिलने का समय तय करने के लिए, जाने से पहले फोन करे ताकि आपका समय बर्बाद न हो।
- अच्छे कपड़े भी पहन कर जाए, ताकि आप दिखा सके कि आप कोई है ।
- डायरी या कॉपी और पेन साथ ले जाए, ताकि आप काम की तारीख व कोई कही हुई बात लिख सके।
- हर कागज़ की 2 फोटोकॉपी ले जाए, एक अफ़सर को देने के लिए व एक साइन करके वापस अपने पास रखने के लिए ।
- जो भी कागज़ात, दस्तावेज़ या चिट्ठी जो जमा करनी है (तलिका में पीले खाने को देखिए), उसकी असली वाली और उसकी 2 फ़ोटोकापी ले जाए ताकि आप असली वाली अफ़सर को दिखा सके लेकिन उसे असली कॉपी न दे।
- अफ़सर आपको कई बहाने दे सकते है ! इसके लिए तैयार रहें, और बहाने सुनकर आप गुस्सा न हो।
- अपने अधिकार को जान ले (तलिका में हरे खाने को देखिए) । अगर अधिकार मिलने के लिए कोई फीस, लगती है, तो उस के लिए पैसे ले कर जाए।
- दफ़्तर का नाम और पता जान लीजिए (तलिका में पीले खाने को देखिए), ताकि समय पर पहुंचें ।
- पहले से ही सोच कर जाइए कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए, तो हमारे **अगले कदम क्या होगा**।
- अधिकारी के ऊपर बडे अधिकारी का नाम जानें (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए), ताकि **अगर आवश्यक हो, तो उच्च प्राधिकरण के पास ले जा** सकें।
- पहले से सोच ले कि कौन क्या बात करेगा, ताकि सब लोग एक साथ न बोलने लगे ।

मीटिंग के दौरान

- अपना परिचय दे । अगर हो सके, उनका नाम, पद और फोन नम्बर भी पूछ कर लिख लेना।
- अपना आने का कारण साफ़ शब्दों में बताए और उन्हें पहले ही बोल दे कि आप उनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
- जो भी कागज़ात या आवेदन देना है तो अपनी एक कॉपी पर "रीसीव्ड" मोहर ज़रुर लगवाए।
- यदि अफ़सर बहाने बनाए तो खामोश रहे, ऊची आवाज़ में न बोले। अगर झगड़ा होता है तो इसमें आपका ही नुक्सान होगा।
- जो कुछ भी अफ़सर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना। उम्मीद हैं कि फिर वो अपनी अकारण प्रतिक्रियाए खुद महसूस करेगा।
- अगर कर्मचारी कहते है कि "बाद में देखेंगे" तो तारीख ज़रुर तय कीजिए, और वह तारीख अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
- साफ़–साफ़ बताए कि अगर अपका काम नहीं होता है तो आप क्या **अगले कदम लेंगे** (6वी कदम देखो) और कब तक, मगर गुस्सा न हो।
- जाते समय शुक्रिया ज़रूर कहिये। एसे कहने से, उम्मीद है कि अगली बार वह अफ़सर अपकी मदद करेंगे।

अगर कर्मचारी एक अनधिकृत भुगतान मांगे

- उससे पूछे कि इस पैसे के बारे में कहाँ लिखा है, ताकि उसकी गलती पर रोशनी पड़े ।
- उससे कहें कि आप पैसे देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्ची दे – वह कुछ भी लिखने से डर जाएगा।
- उसकी मांग को ज़ोर से दोहराएँ ताकि आस–पास के लोग सुन सकें और उसे शर्म आए ।
- अगर वो फिर भी मांगे तो उसके सामने उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें– नाम, पद, चेहरा, वह कहॉ बैठता हैं वगैरा–वगैरा।
- अगर फ़िर भी धूस मांगे तो उसकी शिकायत उससे बड़े अफ़सर से लिखित रूप में करें।

मीटिंग के बाद, लिख लेना ताकि याद रहे:

- मीटिंग की तारीख और समय,
- किससे मिले, उसके नाम और पद,
- क्या नतीजा हुआ मीटिंग में। जो भी काम सरकारी कर्मचारी ने कहा कि वह करेगा, और कब तक।
- जो भी कोई कागजात दिए या लिए है उसकी एक अलग फ़ाइल बना ले और ठीक से रख लें।
- अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम न करे, तो आप क्या करेंगे, और कब तक।

फिर सुनिश्चित करें कि आप कोई भी कार्रवाई करें जो आपने कहा था कि आप करेंगे (आरटीआई दाखिल करें आदि) उस तारीख तक जो आपने कहा था।

5. अगर ज़रुरत पड़े तो किसी उच्च प्राधिकरण के पास जाएं

याद रखें कि आवेदन पत्र में, आपने लिखा है कि आप कब तक कार्रवाई करना चाहते थे । सड़क बनाने, आधार कार्ड बनाने या आंगनबाड़ियों शुरू करने में समय लगता है। सरकारी अधिकारियों को काफी लोगों का काम करना है। इसलिए उचित समय का इंतज़ार करें (तलिका में नीले खाने को देखें)। जब उसका समय खत्म होने वाला हो, तब अधिकारी को एक फोन कर दे, उसे समय सीमा की याद दिलाने के लिए! अगर उचित समय का इंतज़ार करने के बाद आपका काम नहीं हुआ है, तो आप अगले कदम लो दोबारा से सामुदायिक मीटिंग बुलाए और चर्चा करे कि, कि किस तरीकों का अगले कदम लेंगे। कई अलग–अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे (सबसे आसान से सबसे कठिन):

- हो सके तो ऑन लाइन अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें। जैसे कि पेंशन यहां और आधार यहां।
- एक बार फिर से उस अधिकारी से शिकायत करें जहां आपने आवेदन किया था।
- सरकार की शिकायत करने का तरीका इस्तेमाल करें (यहां देखें)।
- केंद्रीय सरकार के योजना में संभावित भ्रष्टाचार के लिए सी बी आई को कॉल करें (9839 017772 या 9415 012635) फोन करें ।
- बड़े अफ़सर से शिकायत करें (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए)।
- उस विभाग में जहां पहले आवेदन दिया था, एक आर.टी.आई. डालें, आप यह ऑनलाइन गुमनाम रूप से यहाँ कर सकते हैं यहां। या लिखित रूप में। नीचे का नमूना देखिए।
- एक गैर सरकारी संगठन, जो उस क्षेत्र में काम करती हो , (जैसे जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल) उनसे संपर्क करें।

<u>(आर टी आइ का नमूना केवल मोटे अक्षरों को बदलना है)</u>

सेवा में
जन सूचना अधिकारी
<u>समेकित बाल विकास योजना</u>
<u>फतेहपुर जिला</u>
<u>उत्तर प्रदेश</u>

1 जनवरी, 2026

<u>विषयः आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन</u>
<u>शिवारामपुर के लिए आंगनवाडी</u> के सम्बंध में जानकारी हेतु

महोदय,

1. मैंने अपने गॉव **<u>शिवरामपुर के लिए आंगनवाडी</u>** के लिए **<u>1 जुलाई 2025 को</u>** आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवही नहीं की गई है। इसलिए कृपया करके निम्नलिखित जानकारी दे।
2. आपके विभाग के नियम और उपनियम के अनुसार, **<u>आंगनवाडी</u>** के लिए हेतु कितना समय लगना चाहिए ?
3. मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराई जाए। इस अवधि में मेरा आवेदन जिस अधिकारी के पास था उसका नाम और पद उपलब्ध कराया जाए। उस अधिकारी के पास कितने समय तक मेरा आवेदन रहा और उस अवधि में उसने उस पर क्या कार्यवाही की ?
4. जिस अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और देरी का कारण बना, उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? ये कार्यवाही कब तक की जाएगी ?
5. शिवरामपुर अपनी **<u>आंगनवाडी</u>** कब तक प्राप्त कर पाएगी ?

मैं इस आर टी आई के साथ आवेदन शुल्क (रु. 10) अलग से जमा कर रहा हूं।

अगर आपको लगता हैं कि ये सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो कृपया आर टी आई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद का 6(3) अनुपालन करें। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार कृपया अपने विभाग प्रथम अपील अधिकारी का विवरण (नाम व पद) अनुरोध किए गए उक्त जवाब के साथ हमें प्रदान करने की कृप्या करें ताकि मैं जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील दायर कर सकूं।
धन्यवाद
<u>रामेश कुमार,</u>
<u>मकान न 6, गली न 7,</u>
<u>शिवारामपुर गॉव, ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश,</u>
<u>टेलीफोन 9750 478 598</u>
<u>हमने यह आर टी आई उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास योजना को भी भेजी हैं ।</u> (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए)

6. कदमः अपने काम का मूल्यांकन!

यदि, उच्च प्राधिकरण के पास जाने के बाद, आप अभी भी सफ़ल नहीं हुए हैं तोः

- अपने साथियों के साथ बैठो और चर्चा करो, की आपने अबतक क्या अच्छा किया है, और क्या बेहतर कर सकते थे ।
- यह देखें कि क्या आप एक दूसरा उच्च प्राधिकरण के पास जा सकते हैं, या आपको किसी की मदद की आवश्यकता है।
- आधिकार प्राप्त करने के लिए एक नई योजना बनाएं।
- नई योजना पर काम करें। हम इसे एक एक्शन–रिफ्लेक्शन चक्र कहते हैं: योजना बनाना, मूल्यांकन करना, योजना बनाना, मूल्यांकन करना, आदि

7. सफ़लता मिलने पर सब के साथ खुशी मनाओ

उम्मीद हैं कि इन 7 कदमों को पूरा करने से आप को आखिर में अपने अधिकार मिल ही जाऐगें, और सब को उस के फायदे मिलेगे। अगर यह हो जाए तोः

- सब लोग जिन्होने मदद की उन के साथ खुशी मनाओ । सब को समोसे और मिठाई खिलाओ !
- जिस अफ़सर ने अच्छा काम किया, उनको शुक्रिया जरुर कहिए। उसको अच्छा भी लगेगा, और शायद वह बाद में और मदद करेगा।
- दूसरे गाँव व बस्ती वालों को अपनी सफ़लता के बारे में जरुर बताए और अगर वह भी ऐसे ही कोशिश करना चाहते हैं, उनको भी मदद करें।
- दुबारा सब लोगों के साथ मिल कर फ़ैसला कीजिये कि अब अगली कौनसी समस्या को ले ताकि उस समस्या के साथ आप फिर से वैसे ही शुरूआत करे । यानी आप पहले कदम से काम फ़िर शुरू करे ।

सफ़लता की कहानियाँ

<u>राजू को विकलांगता पेंशन मिलती है</u>

राजू, एक रेलवे ट्रैक के किनारे से एक झोंपड़ी में रहता है । 5 बच्चों का पिता होने के नाते, वह कबाड़ी का काम करता है जिससे वह ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। एक पर्याप्त शारीरिक विकलांगता होने के बावजूद–उसके बाये पैर में फालिज है और पैर मुड़ा हुआ है –वह अपने काम के लिए कई किलोमीटर साइकिल से जाता है । जब हमारे समुदाय के कार्यकर्ता, राजू से मिले तो राजूं ने उनके लिए विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करने को कहा। वह पहले व्यक्ति थे, जिसके लिए समुदाय के कार्यकर्ता ने आवेदन किया था, इसलिए सिस्टम सीखने में कुछ समय लगा–उनके दस्तावेजों की फोटो लेना, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना और जिला विकलांग कल्याण कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करना । कई महीनों के इंतजार के बाद राजू को नवंबर 2020 में पहली किस्त मिली! 500 रुपये (USD $7) प्रति माह ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो है । राजू की सफलता के बाद से कई अन्य लोग विभिन्न प्रकार की पेंशन (विकलांगता, विधवा और वृद्धावस्था) के लिए आवेदन करने की मांग करते हुए आगे आए हैं ।

<u>रूबी एक गैस कनेक्शन हो जाता है</u>

रूबी, 24 साल, एक रेलवे ट्रैक के किनारे से एक झोंपड़ी में रहती है उनकी 3 साल की बेटी और उनके पिताजी के साथ । वह घर के अंदर एक लकड़ी के चुल्हे पर खाना पकाती थी, जो उसके लिए कष्ट दायक और समय लेने वाला था, और उसकी बेटी और बुजुर्ग पिता के लिए साँस लेने में मुश्किल होती थी। वह गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पैन कार्ड और बैंक खाता (एक सरकारी गैस कनेक्शन के लिए आवश्यकताएं) और पैसे नहीं थें। हम उसे दोनों एक पैन कार्ड और एक बैंक खाते के लिए आवेदन करने में मदद की, और फिर स्थानीय गैस वितरक को उसके दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करवाई, साथ ही साथ थोड़े पैसो की मदद भी की (डिपोज़िट के लिए)। अब रूबी एक साफ़, सस्ता और अधिक सुविधाजनक ईंधन पर खाना पकाने के साथ–साथ समय, पैसे, और उसके फेफड़ों को बचाती है ।

<u>प्रिय को 2 साल का राशन मिला</u>

उत्तराखंड में एक एनजीओ ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। सत्र के दौरान, प्रिय ने खुलासा किया कि उसके परिवार को पिछले दो वर्षों से राशन से वंचित रखा गया था। एनजीओ ने उसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। प्रिय ने तुरंत हेल्पलाइन के टोल–फ्री नंबर 1905 पर कॉल किया। सभी को आश्चर्य हुआ, प्रिय को तुरंत प्रतिक्रिया मिली, और उसकी शिकायत दर्ज की गई। अगले ही दिन, आपूर्ति अधिकारी ने प्रिय से संपर्क किया और शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया। लेकिन प्रिय ने अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा कि जब तक उसका राशन कार्ड जारी नहीं होता और बकाया राशन नहीं मिलता, वह नहीं हिलेगी। अंततः आपूर्ति अधिकारी ने सहमति जताई, राशन कार्ड जारी करने और राशन प्रदान करने का वादा किया। कई दिनों बाद, प्रिय को उसका राशन कार्ड और दो साल का राशन मिला!

यह गाइड बुक इस सनस्था की मदद से बनाई गई है:

- EFICOR www.eficor.org

यह क्रिएटिव कॉमन्स के तहत कॉपीराइट है, जिसका अर्थ है कि यदि आप सामग्री पसंद करते हैं, तो आप इसे किसी भी तरह से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं जो पैसा कमाने नहीं है, जब तक आप ऊपर दिए गए की सनस्था का काम का श्रेय देते हैं, और दूसरों को स्वतंत्र रूप से अपने काम का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।